Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

भारत में हरित क्रान्ति का किसानों के सामाजिक–आर्थिक स्तर पर प्रभाव

डॉ0 विमलेश मिश्र
असिस्टेण्ट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
कृषक (पी0जी0) कॉलेज, मवाना, मेरठ,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ (उत्तर प्रदेश)

सारांश – कृषि में होने वाले पूँजी निर्माण के सन्दर्भ में सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते है। कि आय वृद्धि के साथ कृषक अपने जोत के आकार में वृद्धि करना चाहते हैं। भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण और सामान्य आर्थिक विकासजन्य आय वृद्धि के कारण यह स्पष्ट हो चुका है कि भूमि कीमतें लगातार बढ़ती गई हैं। इस कारण भूमि के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ना स्वाभाविक है। यह भूमि क्षुधा बड़े कृषकों के साथ–साथ आय बढ़ने पर ग्रामीण दस्तकारों और कृषि श्रमिकों में भी बढ़ी है। हरित क्रान्ति की सफलता वाले क्षेत्रों में कृषि उपकरण, मशीनरी, फार्म हाउस और भूमि उद्धरण पर अधिक जोर दिया गया है।
मुख्य शब्द– हरित क्रान्ति, किसान, सामाजिक–आर्थिक, प्रभाव।

प्रस्तावना–भारत सरकार ने 1959 के अन्त में 'जिला सघन कृषि कार्यक्रम' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़ जनपद को चुना। हरित क्रान्ति से हमारे समाज में व्याप्त गरीबी, भुखमरी तथा कुपोषण जैसी समस्याओं को समाप्त करने में सहायता मिल रही हैं भारत में हरित क्रान्ति के सर्वाधिक प्रसार का श्रेय स्वं0 प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया जा सकता है। जिन्होंने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया, जिसके अनुसार देश को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने का काम सैनिकों का है जबकि खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किसानों का है। उनका यह सन्देश 1967–68 में रंग लाया जब कृषि उत्पादन तेजी से बढने लगा।

हमारे देश में वास्तव में हरित क्रान्ति कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उन्नतशील बीज, कृषि के सुधरे तरीके, रासायनिक खादों एवं दवाइयों तथा नहरी सिंचाई प्रणाली एवं मशीनों का प्रयोग एक साथ किया जाने लगा। जिसे 'पैकेज कार्यक्रम' कहा गया। दो वर्ष पश्चात् इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाने के लिए 'गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम' का स्वरूप निर्धारित हुआ। जिसके अन्तर्गत कुछ विशेष प्रकार की फसलों को

ध्यान में रखा गया। कृषकों को कृषि सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान और उत्पादन बढ़ाने के अन्य साधन भी आवश्यकता एवं समतानुसार व्यवस्थित किये गये। हरित क्रान्ति के प्रमुख कार्यक्रमों को दो भागों में बाँटकर मूल्यांकित किया जा सकता है–

हरित क्रान्ति के प्रमुख कार्यक्रम

(अ) कृषि तकनीकी एवं संस्थागत सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम	(ब) कृषि उत्पादन में सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम
(1) आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग	(1) रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों का प्रयोग
(2) सिंचाई सुविधाओं का विकास	(2) उन्नतिशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि
(3) भूमि परीक्षण कार्यक्रम	(3) बहुफसली कार्यक्रम
(4) पौध संरक्षण कार्यक्रम	(4) कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि
(5) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना	(5) कृषि उपजों का सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण
(6) कृषि उद्योग निगम	(6) पूंजी तथा बाजार की व्यवस्था
(7) कृषि विकास हेतु विभिन्न निगमों की स्थापना	(7) कृषि बचतों को प्रोत्साहन
(8) ग्रामीण विद्युतीकरण	
(9) भूमि संरक्षण	
(10) कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान	

हरित क्रान्ति के द्वारा कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों को निम्नलिखित रूपों में मूल्यांकित किया जा सकता है–

(1) कृषि के क्षेत्र में हरित क्रान्ति को अंगीकार किये जाने के पश्चात् फसलों एवं पशुओं का अनुपात असीमित होने लगा। कृषि के अधिकांश काम मशीनों द्वारा उच्च तकनीकी युक्त यन्त्रों से प्रारम्भ किये गये जो न केवल कम खर्चीले हैं वरन् कार्य को शीघ्र समाप्त करने की क्षमता भी रखते हैं। कृषि उत्पादनों पर मशीनों का प्रभाव भी इस रूप में सफल रहा है।

(2) हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिए पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाओं के विकास पर विशेष बल दिया गया। चूंकि उन्नतशील बीजों की उत्पादकता अल्प लागत वाली सिंचन सुविधाओं पर निर्भर करती है। यही कारण रहा है कि सन् 1970 से 1980 के दशक में भारत सहित विश्वविद्य के अधिसंख्य देशों द्वारा 'नहरी सींच प्रणाली' को विकसित किया गया है।

(3) हरित क्रान्ति कार्यक्रम में कृषि में नई रणनीतियों के तहत् भूमि परीक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी का पारिस्थतिक परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। इस

परीक्षण का मुख्य उद्देश्य भूमि की उर्वर शक्ति का पता लगाकर कृषकों को उनके अनुरूप रासायनिक खादों व उत्तम बीजों के प्रयोग की सलाह देना है। इस कार्यक्रम के तहत वर्तमान समय में सरकारी प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख, नमूनों का परीक्षण किया जाता है।

(4) हरित क्रान्ति के अन्तर्गत पौध संरक्षण का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके लिए भूमि तथा फसलों पर दवा छिड़कने का कार्य किया जाता है ताकि खरपतवार से फसलों की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में घातक टिड्डी दलों पर नियंत्रण करने तथा उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में समेकित कृषि प्रबन्ध के अन्तर्गत पारिस्थितिकी अनुकूल भूमि नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया है।

(5) सरकार ने कृषकों में व्यवसायिक साहस की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने की एक योजना लागू की है। इसमें पहले कृषकों को भलीभाँति प्रशिक्षित किया जाता है और फिर इनसे कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए उनको राष्ट्रीयकृत बैंकें से वित्तीय सहायता दिलाई जाती है।

(6) हरित क्रान्ति के अन्तर्गत सरकार ने अपनी नीति के तहत 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई हैं। इन निगमों का मुख्य कार्य मशीनरी तथा कृषि उपकरण की पूर्ति तथा फसल के प्रसंस्करण एवं भण्डारण को प्रोत्साहन देना है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए कृषि उद्योग निगम द्वारा किराया क्रम पद्धति के आधार पर ट्रैक्टर, पम्पसेट एवं अन्य मशीनरी को वितरित किया जाता है।

(7) हरित क्रान्ति की प्रगति मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती हैं– (i) अधिक उपज देने वाली किस्में, (ii) उत्तम सुधरे हुए बीज। इसके लिए 4,000 कृषि फार्म स्थापित किये गये हैं और 1963 में एक निगम राष्ट्रीय बीज निगम के नाम से स्थापित किया गया है। इसी प्रकार के निगम 13 राज्यों में स्थापित किये गये हैं।

(8) ग्रामीण जन–जीवन का स्तर उठाने तथा कृषि के लिए विद्युत उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना लागू की गई हैं। 1951 में केवल 3,061 गाँवों में ही बिजली थी लेकिन आज 5 लाख 9 हजार गाँवों में बिजली पहुँच गयी है। गाँवों को बिजली देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई है। हरित क्रान्ति के अन्तर्गत भूमि संरक्षण का कार्यक्रम अपनाया गया है जिसके प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं– (i) कृषि योग्य भूमि को क्षरण से रोकना तथा (ii) उबड़–खाबड़ भूमि को समतल बनाकर खेती योग्य बनाना। यह कार्यक्रम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में तेजी से लागू किया गया है।

(10) हरित क्रान्ति लाने में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार का योगदान भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः हरित क्रान्ति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे उस तकनीक को अपनाकर कृषि उत्पादन बढ़ा सकें। हरित क्रान्ति लाने में अभी तक मुख्य रूप से

गेहूँ व चावल की प्रजातियों का ही योगदान रहा है। अतः अन्य फसलों की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के लिए अनुसंधान कार्य भी आवश्यक है। साथ ही असिंचित दशाओं में कृषि उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

भारत में हरित क्रान्ति उत्पादन में सुधार निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये गये हैं–

(1) हरित क्रान्ति के पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत आदर्श फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों एवं दवाओं के अधिक प्रयोग पर बल दिया गया। परिणामतः कम दिनों में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की उन्नतशील प्रजातियों से उत्पादन भी बढ़ा।

(2) अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग बढ़ा और नयी–नयी किस्मों की खोज की गई जैसे– गेहूँ से सेनारा 64, लरमा, रोजो 64–ए, कल्याण सोना; चावल में छोटा बासमती, नयी जय, पदमा, रत्ना, जिया, विजया, कृष्णा आदि। अभी तक अधिक उपज देने वाला गेहूँ, धान, बाजरा, मक्का व ज्वार पर भी ही लागू किया गया है लेकिन गेहूँ में सबसे अधिक सफलता मिली है। नई विकास विधि के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में किसानों के बीच 5,100 हजार कुन्तल प्रजनक बीज, 700 हजार कुन्तल आधार बीज तथा 12,740 हजार कुन्तल अन्य प्रमाणित बीज वितरित किये गये।

(3) बहुफसली कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि के समस्त साधनों एवं तकनीकों का प्रयोग करके एक ही भूमि पर कई फसलें उगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

(4) भारतीय कृषि में लागू की गई नई विकास विधि 'हरित क्रान्ति' का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि देश में फसलों के अधीन क्षेत्रफल, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हो गई। विशेषकर गेहूँ, बाजरा, धान, पक्का तथा ज्वार के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर सा हो गया है।

(5) हरित क्रान्ति का आवश्यक तत्व कृषि उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारण है। इसी सन्दर्भ में सरकारों ने मूल्य निर्धारण समिति का गठन करके एक समर्थन मूल्य की अवधारणा विकसित की जिससे प्रत्येक किसान को उचित मूल्य पर न मात्र सुविधाएँ प्रदान की गई वरन् उपजों का भी उचित मूल्य दिया जाने लगा।

(6) हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से धन, तकनीकी एवं यंत्रों की सुविधा किसानों तक नियोजित ढंग से पहुँचाई गई। साथ ही मण्डी परिषदों की स्थापना करके बाजार भी सुनिश्चित किये गये जिससे किसान अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर विक्रय कर सकें।

(7) उन्नत बीज, रासायनिक खादें, उत्तम सिंचाई साधन व मशीनों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा है जिससे कृषक के पास बचतों की मात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जिसको देश के विकास के काम लाया जा सका। इससे औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति हुई है, उत्पादन बढ़ा है।

हरित क्रान्ति के पश्चात् देश में कृषि गत अर्थव्यवस्था पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा है। हरित क्रान्ति के प्रभावों का दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है–

हरित क्रान्ति के आर्थिक व सामाजिक प्रभाव

आर्थिक प्रभाव	सामाजिक प्रभाव
(1) कृषि उत्पादन में वृद्धि	(1) पूँजीवादी कृषि का विकास
(2) कृषि उत्पादकता में वृद्धि	(2) क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि
(3) रोजगार में वृद्धि	(3) भूमि–सुधार पर प्रभाव
(4) कृषि बचतों में वृद्धि	(4) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि
(5) आयात प्रतिस्थापना तथा निर्यात सम्बर्द्धन में सहायक	(5) ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन
(6) औद्योगिक क्षेत्र में निर्भरता	(6) उपभोक्ताओं पर प्रभाव
(7) कीमतों पर प्रभाव	(7) विचारधारा में परिवर्तन
(8) आर्थिक विकास का आधार	
(9) किसानों की संवृद्धि	

आर्थिक प्रभाव–

प्रमुख आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं–

(1) कृषि उत्पादन में वृद्धि– भारत में गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि की फसलों के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रसार से 1965–66 के पश्चात् इनका उत्पादन तेजी से बढ़ा है। नई कृषि नीति के परिणामस्वरूप यद्यपि विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु सबसे अधिक वृद्धि गेहूँ के उत्पादन में हुई है। इसलिए प्रायः कहा जाता है कि हरित क्रान्ति वास्तव में 'गेहूँ की क्रान्ति' है।

(2) कृषि उत्पादकता में वृद्धि– यदि हम यह मान लें कि कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र की मात्रा में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है तो कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रमुख कारण प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि को जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, चावल की प्रति हेक्टेयर उपज 1960–61 में 1,013 किग्रा थी जो बढ़कर 2001–02 में 2,085 किग्रा हो गई। इसी प्रकार गेहूँ के प्रति हेक्टेयर उपज 1960–61 में 851 किग्रा थी जो 2001–02 में बढ़कर 2,770 किग्रा हो गई।

(3) रोजगार में वृद्धि– नई कृषि नीति के अनुसार विकसित कृषि रीतियाँ श्रम प्रधान समझी जाती हैं। नई कृषि नीति के अन्तर्गत खेतों का समय–समय पर सिंचित करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह खेतों पर उर्वरक लगाने, कीटाणुनाशक दवाइयों तथा अन्य क्रियाओं के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। दो या दो से अधिक फसलों के कारण तथा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप परिवहन बिक्री तथा विपणन आदि की सेवाओं की माँग में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि हुई है।

(4) कृषि बचतों में वृद्धि– हरित क्रान्ति के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है जिससे कृषकों की बचतों की मात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस कृषि अतिरेक को देश के विकास के लिए काम में लिया जा सकता है।

(5) आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात सम्बर्द्धन में सहायक– हरित क्रान्ति के कारण कृषिजन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होने से इनके आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी।

(6) औद्योगिक क्षेत्र में निर्भरता– नई कृषि नीति में उद्योगों द्वारा निर्मित कृषि आदानों का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मशीन और उपकरण, उर्वरक, कीटाणुनाशक दवाइयाँ आदि की पूर्ति के लिए कृषि औद्योगिक क्षेत्र पर पूरी तरह से निर्भर है। यह निर्भरता धीरे–धीरे बढ़ती जा रही है।

(7) कीमतों पर प्रभाव– तीसरी योजना में कीमतों पर और विशेष रूप से कृषि पदार्थों की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई परन्तु हरित क्रान्ति के फलस्वरूप इस वृद्धि की गति कम हो गई है।

(8) आर्थिक विकास का आधार– भारत में वर्तमान समय में 18.5 प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है वहीं 16 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं को निर्यात किया जाता है। निर्यात कृषि वस्तुओं से जहाँ सरकारी बजट तथा यातायात पर कृषि का अधिक प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि से देश के आर्थिक विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों की पूर्ति से सहायता मिली है।

(9) किसानों की संवृद्धि– हरित क्रान्ति के फलस्वरूप किसानों की अवस्था में काफी सुधार हुआ है। उनका जीवन–स्तर पहले से बहुत ऊँचा हो गया है।

सामाजिक प्रभाव–

(1) पूँजीपति कृषि का विकास– नई कृषि नीति उत्पादन–विधि के कारण भारत में पूँजीवादी कृषि का विकास हो रहा है क्योंकि अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उपज और सिंचाई में भारी विनियोग करना पड़ता है जो छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानों की सामर्थ्य से परे हैं। भारत में 12 प्रतिशत बड़े किसानों के पास कुल भूमि का 50 प्रतिशत है और ये ही 12 प्रतिशत बड़े किसान नलकूप, पक्पिंग सेट, उर्वरक और भारी मशीनरी के रूप में भारी विनियोग कर रहे हैं। परिणामतः नवीन कृषि विधि से निर्धन किसानों को लाभ नहीं हुआ है बल्कि इस कारण ग्रामीण जनसंख्या के उच्चतम 10वें भाग के हाथ में सम्पत्ति का संकेन्द्रण हुआ है। अशोक रूद्र, माजिद और तालिब ने पूँजीवादी खेती का विश्लेषण करने के लिए पंजाब के बड़े किसानों का अध्ययन किया और निष्कर्ष पर पहुँचे कि नई कृषि उत्पादन विधि के कारण पूँजीवादी खेतों का विकास हुआ है।

(2) क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि– भारत में हरित क्रान्ति से क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। अधिक उपज देने वाले बीजों और उर्वरकों के प्रयोग से केवल गेहूँ के प्रति हेक्टेयर उपज में तो वृद्धि हुई है, परन्तु अन्य किसी फसल पर इस योजना का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में और विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े किसानों की सम्पन्नता बढ़ने से कृषि से भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो

चली है, जबकि देश के अन्य सभी भागों में कृषि का स्वरूप परम्परागत बना हुआ है। अतः कहा जाता है कि ''हरित क्रान्ति से निर्बलता के सागर में सम्पन्नता के द्वीप बन गये हैं।''

(3) भूमि–सुधार पर प्रभाव– हरित क्रान्ति ने ग्रामीण में धनी किसानों के एक शक्तिशाली वर्ग को सशक्त बनाया है। बड़े किसान न केवल आर्थिक रूप से, वरन् राजनीतिक दृष्टि से भी अधिक शक्तिशाली हो गये हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि–सुधार को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि बड़े किसान क्रियान्वयन में बाधा डालने में सफल रहे। इस स्थिति का विपरीत प्रभाव छोटे कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों पर पड़ा।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि– हरित क्रान्ति के अन्तर्गत गहन कृषि विकास कार्यक्रम को अपनाया गया है और कृषि के परिणामस्वरूप यन्त्रीकरण में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है।

(5) ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन– ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जुई बेरोजगारी के फलस्वरूप ग्रामीण जनसंख्या के शहरों में जाने से वहाँ स्थानीय यातायात, आवास एवं जन–स्वास्थ्य की समस्याएँ अधिक विकट हो गई है। जिनके सामाजिक परिणाम बहुत बुरे होंगे।

(6) उपभोक्ताओं पर प्रभाव– भारत में निर्धन जनता की लगभग 80 प्रतिशत आय कृषि पदार्थों पर व्यय की होती है। इसलिए यहाँ कृषि पदार्थों के उत्पादन और उनकी कीमतों में होने वाले परिवर्तन का उपभोक्ता के बजट और जीवन–स्तर पर काफी प्रभाव पड़ता है। हरित क्रान्ति उनके बजट को सन्तुलित करने और जीवन–स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध हुई है।

(7) विचारधारा में परिवर्तन– भारत जैसे अर्द्धविकसित देश में जहाँ अधिकतर किसान अनपढ़, रूढ़िवादी और अन्धविश्वासी होते हैं, हरित क्रान्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हरित क्रान्ति ने भारतीय गाँवों में विचारों की क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। अब लोग यह समझने लगे हैं कि विज्ञान की सहायता से वे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। भारतीय किसानों ने जिस शीर्घता से कृषि की इस नई तकनीकी को अपनाया गया उससे यह प्रमाणित होता है कि भारतीय कृषक ऐसी विचारधारा की प्रतीक्षा में ही था।

निष्कर्ष–कृषि में होने वाले पूँजी निर्माण के सन्दर्भ में सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते है। कि आय वृद्धि के साथ कृषक अपने जोत के आकार में वृद्धि करना चाहते हैं। भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण और सामान्य आर्थिक विकासजन्य आय वृद्धि के कारण यह स्पष्ट हो चुका है कि भूमि कीमतें लगातार बढ़ती गई हैं। इस कारण भूमि के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ना स्वाभाविक है। यह भूमि क्षुधा बड़े कृषकों के साथ–साथ आय बढ़ने पर ग्रामीण दस्तकारों और कृषि श्रमिकों में भी बढ़ी है। हरित क्रान्ति की सफलता वाले क्षेत्रों में कृषि उपकरण, मशीनरी, फार्म हाउस और भूमि उद्धरण पर अधिक जोर दिया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. Agrawal, A.N. (1988) : 'Problems of Development and Planning', Wiley Eastern Limited, New Delhi
2. Banerjee, P.K. (1977) : 'Indian Agriculture Economy : Financing Small Farmers', Chetna Publications, New Delhi. (Revised Edition 2008, 2010)
3. Bansil, P.C. (1977) : 'Agricultural Problems of India', Vikas Publishing House Ltd., New Delhi. (Revised Edition 2010)
4. Mahajan, V.S. (ed.) (1990) : 'Agricultural and Rural Economy in India', Deep and Deep Publications, New Delhi. (Revised Edition 2010)
5. Sadhu, A.N. and Amarjit Singh, (1983) : 'Fundamentals of Agriculture Economics', Himalaya Publishing House, Mumbai. (Revised Edition 2010)
6. Subrata Ghatak and Ken Ingersent, Agriculture and Economic Development (New Delhi 1984).
7. W.R.C. Gopalan and S.C. Balasubramanian (1966) : The Nutrative Value of Indian Foods and the Planning of Satisfactory Diets. ICAR, New Delhi